e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

IJIRSET

International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 11, Issue 7, July 2022

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 8.118

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET)

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 7, July 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1107103 |

भारत की राजनीति में कोरोना का प्रभाव

Dr Anchal Meena

Political Science, BSR Govt. College, Alwar, India

सार

प्रधानमंत्री नरेंद्र ने अपने कई संबोधनों में 'संकट को अवसर' में बदलने की बात कही है और ये महामारी केंद्र के लिए और मोदी प्रशासन के लिए वाकई किसी अवसर से कम नहीं है.भारत ने दुनिया के कई देशों की तुलना में अपने यहां कोविड19 के प्रसार को नियंत्रित किया है और अगर आने वाले वक़्त में सरकार इसे क़ाबू में रखने में कामयाब होती है तो यह वैश्विक स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी.

हालांकि सरकार के लॉकडाउन के फ़ैसले पर लोगों की राय काफी बंटी हुई है. एक ओर जहां सरकार इसे साहसी क़दम बताती है वहीं एक बड़ा वर्ग मानता है कि पहले लॉकडाउन की घोषणा के पहले लोगों को कुछ वक़्त दिया जाना चाहिए था.सरकार इस मोर्चे पर सफल रही या नहीं ये कहना जल्दबाज़ी होगी लेकिन यह ज़रूर है कि इस दौरान नरेंद्र मोदी का क़द पहले से बढ़ा ज़रूर है.वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक स्मिता गुप्ता कहती हैं "जनवरी महीने तक देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे थे. नागरिकत संशोधन क़ानून को लेकर लोग आवाज़ उठा रहे थे. भले ही कोई राजनीतिक दल खुलकर इनके साथ नहीं खड़ा हो रहा था लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर ही राजनीतिक गतिविधि चल रही थी. लेकिन लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से इन प्रदर्शनों पर एक तरह से विराम लग गया." वो आगे कहती हैं, "दूसरी बात यह हुई कि लॉकडाउन की वजह से इस बात की संभावना भी नहीं रही कि कोई राजनीतिक दल धरना या प्रदर्शन करे. कोई रैली नहीं कर सकता है. ये बात बीजेपी और केंद्र सरकार पर भी लागू होती है लेकिन प्रधानमंत्री जब भी चाहते हैं राष्ट्रीय चैनल और रेडियो के माध्यम से अपनी बात देशवासियों तक पहुंचा लेते हैं. वो जब चाहे तब लोगों को संबोधित कर सकते हैं. ऐसे में प्रधानमंत्री की बात तो लोगों तक पहुंच ही रही है."वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी कहती हैं कि कोविड 19 के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक नई चीज़ ज़रूर हुई है.वो कहती हैं, "प्रधानमंत्री का राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से मिलना वो भी पांच बार, घंटों-घंटों के लिए, नयी बात है. उन्होंने कहा कि स्टेट्स फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं. तो सही मायने में ये नयी बात है. वरना तीन महीने पहले हम और आप शायद ये सोच भी नहीं सकते थे कि मोदी जो केंद्र में दूसरी बार चुनकर आए हैं ऐसा करेंगे..हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे."लेकिन नीरजा विकेंद्रीकरण के उलट केंद्रीकरण की बात भी करती हैं.

वो कहती हैं, "यह बात ग़ौर करने वाली है कि केंद्र में प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय काफी मज़बूत हुआ है. कहीं भी राजनेताओं की भूमिका नहीं दिखती है. यह सही है कि तमाम मीटिंग्स में हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह और अमित शाह बैठे रहते हैं लेकिन आमतौर पर पॉलीटिकल क्लास एकदम बाहर हो गया है. अब सबकुछ पीएम और पीएमओ तक ही सिमट कर रह गया है."नीरजा कहती हैं कि केंद्र में तो यह मॉडल पहले से ही था लेकिन अब राज्यों में भी कुछ ऐसी ही स्थिति दिख रही है.वो कहती हैं, "राज्यों में भी सीएम और सीएमओ ही सबकुछ हो गया है. विधायकों का रोल कहीं भी दिख ही नहीं रहा है."नीरजा कहती हैं जो मोदी मॉडल सेंटर में था अब वो स्टेट्स में भी लागू होता दिख रहा है.

परिचय

कोविड19 केवल मोदी और मोदी सरकार के लिए अवसर नहीं है. विपक्ष के लिए भी है लेकिन कई जगहों पर जहां विपक्ष ने एक गंभीर और सहयोगात्मक विपक्ष होने का प्रमाण दिया है वहीं कई बार विपक्ष कमज़ोर भी नज़र आता है.महामारी के शुरू होने के बाद से जिन भी विपक्षी दलों की तरफ़ से बयान आए है सबने 'आपसी सहयोग से महामारी से निपटने' की बात ही की है. [1,2]

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET)

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 7, July 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1107103 |

सभी राजनीतिक दल इसे एक राष्ट्रीय आपदा के तौर पर देख रहे हैं.लेकिन क्या विपक्ष और ज़िम्मेदारी के साथ सामने आ सकता था?

इस सवाल के जवाब में स्मिता गुप्ता कहती हैं "कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय से संकट से जूझ रही है. राहुल गांधी पिछले साल ही अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे चुके हैं और सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं. ऐसे में पार्टी ख़ुद में असमंजस की स्थिति में है. पार्टी अनिश्चितता से जूझ रही है."

अगर यह स्थिति ना होती तो संभव है कि और बेहतर तरीक़े से चीज़ें सामने आतीं.स्मिता कहती हैं, "जो लोग बीजेपी को पसंद नहीं भी करते हैं वो भी मानते हैं कि यह एक नेशनल क्राइसेस है. तो ऐसे में विपक्ष के दल भी बहुत आक्रोशित होकर सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस समय सबको साथ मिलकर इस महामारी से लड़ना चाहिए."स्मिता कहती हैं "विपक्ष खुलकर नहीं दिख रहा उसका एक बड़ा कारण है कि उनके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है. डिजीटल प्लेटफ़ॉर्म हैं लेकिन क्या उनकी पहुंच उस स्तर की है...?"हालांकि स्मिता कांग्रेस के सरकार और उसकी नीतियों पर उठाए गए सवालों को कोशिश तो मानती हैं लेकिन यह ज़रूर कहती हैं कि विपक्ष खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहा है क्योंकि बाधाएं हैं.स्मिता कहती हैं "ये सही है कि विपक्ष के पास रैली..धरना देने और अपनी बात पहुंचाने क विकल्प नहीं है लेकिन विपक्ष को चाहिे कि जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां वो बेहतर काम करें. क्योंकि अगर वो अपने यहां परिस्थितियों को संभालने में कामयब होते हैं तो उन्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी."

इस विषय पर नीरजा मानती हैं कि एक बड़ी दुविधा विचारों के लिहाज़ से भी है. वो कहती हैं "अगर इस समय में विरोध करेंगे तो लोग कहेंगे कि ऐसे समय में क्या ज़रूरत?"[3,4]

संसद के बंद होने को भी नीरजा एक बड़ा कारण मानती हैं. नीरजा कहती हैं कि अभी बात हो रही है ऑनलाइन वोटिंग की.वो कहती हैं, "भारत में चुनावों के लिहाज़ से बात की जा रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव ऑनलाइन हो सकते हैं. ऐसे में यह एक बिल्कुल नया अनुभव होगा क्योंकि ये पहले कभी नहीं हुआ है हमारे देश में. और इसमें मैन्युपुलेट किये जाने की आशंका से

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 7, July 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1107103 |

भी इनक़ार नहीं किया जा सकता है. लेकिन यहां सोचने वाली बात ये है कि ये संकट कब तक रहेगा ये तो कोई कह नहीं सकता तो क्या भविष्य में बंगाल में, यूपी में भी ऐसे ही चुनाव होंगे? यह सवाल है कि क्या एक नए दौर में हम प्रवेश कर रहे हैं?"

यदि हम आज कोरोना वायरस का नाम सुनते हैं तो, जो वस्तुस्थिति सर्वप्रथम उभरकर सामने आती है वह 'क्वारंटाइन (अपनी गतिविधियों को स्वयं तक सीमित करना) या आइसोलेशन (एकाकीकरण) ' है। यह आइसोलेशन न केवल व्यक्ति या समाज के स्तर पर हुआ है बल्कि विभिन्न देशों की सीमाओं की स्तर पर भी हो गया है। इस वैश्विक आपदा की स्थिति में जहाँ एक ओर युद्ध स्तर पर बचाव के प्रयास किये जा रहे हैं तो वहीँ दूसरी ओर 'फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ (विकसित देश)' के बीच इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी प्रारंभ हो गया है। हाल ही में चीन सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आधिकारिक रूप से यह दावा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन में नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है।[5,6]

संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी पलटवार करते हुए कोरोना वायरस को 'वुहान वायरस या चाइनीज़ फ्लू' के रूप में संबोधित करना प्रारंभ कर दिया है। ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि क्या इस वायरस का प्रभाव भू-रणनीतिक व्यवस्था को परिवर्तित कर देगा? क्या एक बार फिर विश्व शीत युद्ध के दौर में प्रवेश कर जाएगा? क्या 21वीं सदी के आरंभ में विकसित बहुध्रुवीय वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था एकध्रुवीय राजनीतिक व्यवस्था की ओर मुड़ जाएगी?इन परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझने के लिये इस आलेख में कोरोना वायरस तथा उसके स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों के इतर तेज़ी से बदलती वैश्विक भू-राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी।[7,8]

कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत के लिए कई मुसीबतें लेकर आई. इस दौरान एक ओर जहां बहुत से लोगों की जान गई और लाशों को नदियों में बहाने की तस्वीरें सामने आईं, वहीं दूसरी ओर भारत अपनी कई अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियां निभाने से भी चूका. भारत के वैक्सीन निर्यात पर प्रतिबंध के फैसले से जहां 'कोवैक्स प्रोग्राम' धीमा हुआ, वहीं बांग्लादेश जैसे पड़ोसी भी काफी

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 7, July 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1107103 |

परेशान हुए. भारत के वैक्सीन निर्यात पर बैन के फैसले के बाद बांग्लादेश ने अप्रैल अंत में अपनी जनता को कोवीशील्ड की पहली डोज देने पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद उसे चीन ने लाखों वैक्सीन गिफ्ट कीं और अब बांग्लादेश चीन से वैक्सीन खरीद भी रहा है. बांग्लादेश में नई वैक्सीन के तौर पर लोगों को अब 'साइनोवैक' ही दी जा रही है.[9,10]

अब सवाल यह है कि फिलहाल कई समस्याओं से जूझ रहा भारत पड़ोसियों के साथ अपने संबंध फिर से सामान्य कर सकेगा या नहीं? इस मसले पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विदेश संबंधों के प्रोफेसर हैप्पीमोन जैकब लिखते हैं, "भले ही 17 साल बाद भारत को विदेशी मदद स्वीकार करनी पड़ी हो लेकिन भारी मात्रा में भेजी गई मदद दिखाती है कि दुनिया मान रही है कि भारत को नजरअंदाज करना मुश्किल है. लेकिन दूसरी ओर संशय भी है कि जबतक वह फिर अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता, पश्चिमी दुनिया के किसी काम का नहीं होगा. महामारी के चलते नई दिल्ली के दक्षिण-एशियाई इलाके की बड़ी ताकत और नेता होने के दावे को बड़ा झटका लगेगा. आने वाले सालों में भारतीय विदेश नीति पर इसका असर भी पड़ेगा."[11,12]

विचार-विमर्श

वर्तमान में चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर को कोरोना वायरस के केंद्र के रूप में देखा जा रहा था, परंतु चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरोना वायरस की उत्पत्ति संबंधी दावे ने विश्व राजनीतिक व्यवस्था में नई बहस को जन्म दे दिया है।अमेरिका ने भी आधिकारिक रूप से अपनी प्रेस विज्ञप्तियों में इसे वुहान वायरस के नाम से संबोधित किया है। शोधकर्त्ताओं का ऐसा मानना है कि चीन का 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt And Road Initiative-BRI) प्रोजेक्ट' जिसका विस्तार चीन से यूरोप और एशिया महाद्वीप के विभिन्न देशों तक है, इस वायरस के प्रसार का प्रमुख वाहक है।शोधकर्त्ताओं के अनुसार, अपेक्षाकृत रूप से चीन के करीबी देश ईरान ने भी इस वैश्विक आपदा की स्थिति में चीन से सहायता न मांगकर अमेरिकी प्रभुत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता की अपील कर वैश्विक राजनीति के बदलने के संकेत दिये हैं।चीन के बाद कोरोना वायरस के सबसे बड़े केंद्र इटली ने भी BRI प्रोजेक्ट समेत चीन के साथ अपनी सभी आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया है।यूरोप के कई देशों ने चीन के साथ आर्थिक गतिविधियों में प्रतिबंध लगाकर विनिर्माण क्षेत्र में चीन

के एकाधिकार को चुनौती दी है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति में अमेरिका की भूमिका के संदर्भ में चीन के दावे को रूस का साथ मिला है और दोनों देशों ने सामूहिक रूप से इस आपदा से निपटने के लिये अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।रूस के इस कदम से वैश्विक राजनीति में अमेरिका-चीन टकराव बढ़ने के आसार व्यक्त किये जा रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि वायरस के बारे में जानकारी होने के बावजूद चीन ने इस बात को छिपाकर रखा। अमेरिका के इस आरोप का समर्थन कमोबेश दुनिया के सभी हिस्सों से विशेषज्ञों द्वारा किया गया है चीन की लापरवाही का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वायरस के संक्रमण की जानकारी होने के बाद भी चीन ने वुहान में आयोजित होने वाले 'पॉट लक डिनर' समारोह को निरस्त नहीं किया। इस समारोह में शामिल लगभग 40,000 लोगों में दो-तिहाई लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए। हालाँकि चीन का दावा है कि पेशेंट ज़ीरो (ऐसा व्यक्ति जो किसी भी संक्रामक बीमारी का पहला वाहक है) अमेरिकी सेना का एक सैनिक था, जो चीन में आयोजित सैन्य खेलों में हिस्सा लेने वुहान आए अमेरिकी दल का हिस्सा था।चीन के प्रवक्ता के अनुसार, नवंबर 2019 में अमेरिकी सेना के कुछ सैनिकों को निमोनिया जैसी किसी बीमारी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। चीन का आरोप है कि अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने इस घटना की सही तरीके से जाँच नहीं की और इस बीमारी का विस्तार अन्य अमेरिकी सैनिकों तक हो गया।ध्यातव्य है कि चीन ने देश के भीतर कुछ प्रमुख अमेरिकी अखबारों के पत्रकारों पर रिपोर्टिंग करने पर रोक लगा दी है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उक्त अखबारों पर कोरोना से संबंधित ख़बरों में चीन के प्रति आरोपात्मक बातें लिखने का संदेह व्यक्त किया गया था। इसके जवाब में अमेरिका में कार्यरत चीनी समाचार एजेंसियों को अमेरिकी प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया।[13,14]

जबकि चीन की एक महिला पत्रकार ने बताया है कि अमेरिकी प्रशासन जानबूझकर कोरोना वायरस को 'कुंग फ्लू' (कुंग फू चाइनीज़ मार्शल आर्ट की एक विधा है) के रूप में प्रचारित कर नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है।अमेरिका ने इस घटनाक्रम के एक महत्त्वपूर्ण दुष्परिणाम के रूप में चीन का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर एकाधिकार होने की समस्या पर भी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। यह देखा गया था कि दुनिया में वायरस के प्रसार के आरंभिक चरणों में रोकथाम की संभावित सामग्री (यथा-सर्जिकल मास्क) की आपूर्ति चीन द्वारा बाधित की गई थी।

दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश होने के कारण भारत मुश्किल में पड़ोसी देशों की मदद कर सकता है और इस क्षेत्र के देशों से ऐतिहासिक संबंधों के कारण राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल भी कर सकता है. लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद इस इलाके में भारत का प्रभाव लगातार कम हो रहा है. इसकी पड़ोसियों की मदद करने की क्षमता भी काफी प्रभावित हुई है. ऐसे में पड़ोसी देशों के साथ ऐतिहासिक रिश्ते उसके स्थान को बचाए रख सकेंगे, यह कहना मुश्किल है. सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के डायरेक्टर सी उदय भास्कर कहते हैं, "भारत ने अपनी छवि ऐसी बना रखी थी कि वह अपने साथ-साथ पड़ोसियों की वैक्सीन जरूरतों को भी पूरा कर देगा. शुरुआत में उसने ऐसा किया भी. लेकिन फिर उसने अपने पड़ोसियों को अधर में छोड़ दिया. ऐसे में भारत की छवि तो खराब हुई ही है." हालांकि मुंबई विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं सामरिक अध्ययन केंद्र के डायरेक्टर राजेश खरात मानते हैं, "भारत पर वर्तमान में घरेलू दबाव हैं लेकिन भारत जल्द कूटनीतिक वापसी करेगा. पड़ोसी देशों को भी यह रवैया छोड़ना चाहिए कि हर सुविधा खुद से लाकर उन्हें दी जाए."[15,16]

परिणाम

कोरोना संकट के साए में अमेरिका और चीन जैसी दो वैश्विक महाशक्तियों के बीच टकराव से वैश्विक राजनीति पर गंभीर प्रभाव होने की आशंका व्यक्त की जा रही है।इसका पहला प्रत्यक्ष प्रभाव अमेरिका और चीन के बीच हाल ही में संपन्न व्यापार समझौते पर होगा। साथ ही, चीन के इस घटनाक्रम में लापरवाही भरे रुख के कारण दुनिया भर में चीन को संदेह की नज़र से देखा जाने लगेगा।कोरोना वायरस को लेकर दोनों देशों की बीच उत्पन्न टकराव नवंबर 2020 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। इस आपदा ने एक-दूसरे के धुर विरोधी रहे ईरान और अमेरिका को नज़दीक ला दिया है, जिससे तृतीय विश्वयुद्ध के रूप में मंडराने वाला संभावित खतरा टलता नज़र आ रहा है।इस वैश्विक आपदा से निपटने में नाकाम रहे इटली में कुछ समय के भीतर ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संकट भी देखने को मिल सकता है। ऐसा अनुमान है कि इटली को अपनी खोई साख हासिल करने में कई दशक लग सकते हैं क्योंकि इटली एक ऐतिहासिक और पर्यटन गंतव्य रहा है। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन में गठित नई सरकार पर यह संकट आर्थिक व राजनीतिक रूप से अतिशय दबाव उत्पन्न करेगा।कोरोना वायरस के केंद्र के रूप में चीन के विख्यात होने से दुनियाभर में चीन के लोगों के साथ नस्लीय भेदभाव में इज़ाफा होने की आशंका है।चीन के विनिर्माण क्षेत्र को अपना प्रभुत्व पुनर्स्थापित करने में कई दशक तक

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 7, July 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1107103 |

लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है, जिससे उसकी नव-साम्राज्यवादी नीतियों पर विराम लग सकता है। वैश्विक विनिर्माण के नए केंद्र स्थापित करने में अत्यधिक समय और धन की आवश्यकता होगी क्योंकि विश्व के अन्य देशों में चीन के जैसी अवसंरचना और सस्ते श्रम का अभाव है। जर्मनी की चांसलर समेत यूरोप महाद्वीप के अन्य प्रमुख नेताओं का मानना है कि कोरोना वायरस के प्रभाव से पूरे महाद्वीप में प्रथम विश्वयुद्ध के बाद उत्पन्न हुए आर्थिक संकट जैसी परिस्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। कोरोना वायरस से भारत भी अछूता नहीं रहा है। भारत को अपना पूरा ध्यान वायरस के संक्रमण को रोकने में लगाना चाहिये।भारत को आपदा की इस स्थिति में बदलती वैश्विक राजनीति के किसी भी समूह में शामिल नहीं होना चाहिये क्योंकि इससे भारत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता है।भारत को अपने पड़ोसी देशों तथा क्षेत्रीय संगठनों जैसे- सार्क और बिम्सटेक के साथ मिलकर एक विशेष कार्यदल का गठन करना चाहिये ताकि इस आपदा से निपटने की तैयारियों में समन्वय व संचार की कमी न रह जाए। चीन पहले ही अपनी आर्थिक मदद की रणनीति के जरिए भारत को भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित करने की कोशिश कर रहा था. कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने इस प्रक्रिया को तेज करने का काम किया है. चीन को नियंत्रित करने के मसले पर उदय भास्कर कहते हैं, "चीन का तरीका अलग रहा है, वह भारी लोन देकर और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करके जिस तरह से अन्य देशों से संबंध बनाता है, भारत और अमेरिका वैसा नहीं कर सकते."[17,18]
कोरोना ने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बुरी तरह प्रभावित किया है. जिससे भारत की सेना को आधुनिक बनाने का प्लान भी प्रभावित हुआ है. जबकि उत्तरी सीमा पर चीन की आक्रामकता को नियंत्रित करने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी था. भारत की वैश्विक कूटनीति और स्थानीय भू-राजनीति पर भी इसका असर होना तय है. भारत ने तीन अन्य बड़े देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर चीन को नियंत्रित करने के लिए 'क्वाड' नाम का एक संगठन बनाया था. वर्तमान में भारत पर जो दबाव हैं, वे इस संगठन का प्रभाव भी कम कर सकते हैं. हालांकि उदय भास्कर कहते हैं, "क्वाड एक भौगोलिक महत्व रखता है और इसमें भारत को उसकी भू-राजनैतिक स्थिति का फायदा जरूर मिलेगा." ऐसा नहीं है कि भारत के लिए सभी परिस्थितियां नकारात्मक ही हों. गंभीर संकट अपने साथ अवसर भी लाते हैं. भारत भी इस संकट को अवसर के तौर पर भुना सकता है. हैप्पीमोन जैकब लिखते हैं, "कोरोना की पहली लहर के दौरान ही सार्क देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया था. आपसी सहयोग के जरिए भारत पूरे दक्षिण एशिया में स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत तंत्र खड़ा करने का प्रयास कर सकता है, ताकि ऐसी हेल्थ इमरजेंसी का मजबूती से मुकाबला किया जा सके. भारत को आगामी भू-राजनीति को स्वास्थ्य कूटनीति, पर्यावरणीय मुद्दों और स्थानीय संचार से जोड़कर विकसित करना चाहिए."
राजेश खरात भी भारत को स्वास्थ्य कूटनीति की दिशा में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, "सार्क देशों के बीच सहयोग के जो आधार रहे हैं, उनमें स्वास्थ्य एक प्रमुख मुद्दा है. यह सही बात है कि पिछले कुछ सालों में इस पर उतना जोर नहीं दिया गया. लेकिन यह समय दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्वास्थ्य के मूलभूत ढांचे के निर्माण के लिए बिल्कुल सही हो सकता है." खरात कहते हैं, "इसके लिए हर देश से भारत की सीमा पर एक एक्सक्लूसिव मेडिकल जोन (EMZ) बनाया जाना चाहिए, जहां पड़ोसी देशों के नागरिक आकर अपना इलाज करा सकें. इसके लिए उन्हें दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक न आना पड़े और वे वहीं से इलाज कराकर लौट जाएं. यह कदम भारत की छवि को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा."[19,20]

निष्कर्ष

निसंदेह इस संकट से सही तरीके से निपटने वाली महाशक्ति बदलती वैश्विक राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाएगी। वर्तमान में पूरा विश्व एक गंभीर संकट के दौर से गुज़र रहा है। यह समय एक-दूसरे पर दोषारोपण करने का नहीं बल्कि एकजुटता प्रदर्शित करते हुए इस अदृश्य शत्रु से लड़ने का है।

वैश्विक महाशक्तियों को अपने संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करते हुए समस्त प्रयास इस महामारी की हर संभव रोकथाम की दिशा में करने चाहिये, इसके साथ ही भारत से सीख लेते हुए अपने पड़ोसी देशों व उन क्षेत्रीय संगठनों, जिनका वे हिस्सा हैं, की ओर सहायता का हाथ बढ़ाना चाहिये।कोरोना वायरस के रूप में दुनिया के समक्ष एक अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हुआ है और इसका प्रसार जितनी तेज़ी से हो रहा है, वह इसे अधिक चिंताजनक बनाता है। इसलिये इससे निपटने के लिये विश्व का प्रत्येक प्रयास इस महामारी के पूर्णतः उन्मूलन का होना चाहिये।विश्व के सभी देशों को विनिर्माण क्षेत्र व आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न केंद्रों के निर्माण की दिशा में भी कार्य करना होगा। उदय भास्कर ऐसे किसी सुझाव को प्राथमिकता देने की बात से सहमत नहीं हैं. वे कहते हैं, "भारत को सबसे पहले अपने घरेलू क्षमता निर्माण पर ध्यान देना चाहिए. इसकी मजबूती के बाद ही पड़ोसियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए. मसलन जब तक भारत अपने उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की जरूरतों को पूरा करने का काम नहीं

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 7, July 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1107103 |

करेगा, कोई भी दक्षिण एशियाई देश अपनी जरूरतों के लिए भारत पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकेगा." लेकिन एक डर यह भी है कि जब चीन भारत-प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है, क्या भारत सिर्फ घरेलू समस्याओं पर ध्यान सीमित कर सकता है. हालांकि कोरोना के चलते घटे औद्योगिक उत्पादन और बढ़ी बेरोजगारी के बीच भारत के सामने रणनीतिक महत्वाकांक्षाएं सीमित करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है.

ऐसे हालात का चीन फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है. हालांकि राजेश खरात मानते हैं, "चीन इस समय कोई गड़बड़ी नहीं करेगा क्योंकि गलवान विवाद के बाद से ही भारत उसके खिलाफ पर्याप्त आक्रामक रहा है." चीनी आक्रामकता के अलावा भारत पर बाइडेन प्रशासन के अंतर्गत अमेरिका से संबंधों को नई दिशा देने का दबाव भी है. जाहिर है कोरोना महामारी के बाद भारतीय विदेश नीति में काफी बदलाव होंगे. लेकिन जानकार इसमें आशा की एक किरण भी देखते हैं. उनके मुताबिक दक्षिण एशिया दुनिया के ऐसे इलाकों में शामिल है, जिसका अब तक सबसे कम एकीकरण हो सका है और कोरोना महामारी इसके लिए एक बड़ा अवसर पेश कर रही है. भारत चाहे तो इसकी शुरुआत कर सकता है.[21]

संदर्भ

1. "लॉकडाउन में राहत के बाद भी ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रही अर्थव्यवस्था? जानें". जनसत्ता. 13 जुलाई 2020. अभिगमन तिथि 25 जुलाई 2020.
2. ↑ "कोरोना के सामने घुटनों पर आई दुनिया की अर्थव्यवस्था". आज तक. मूल से 29 जून 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 जुलाई 2020.
3. ↑ "आईएमएफ ने कहा, कोविड-19 का लगातार फैलाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा". हिन्दुस्तान लाइव. अभिगमन तिथि 25 जुलाई 2020.
4. ↑ "कोरोना वायरस के कारण भारत में पैदा हुईं आर्थिक चुनौतियां". ORF. मूल से 10 मई 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 जुलाई 2020.
5. ↑ Ward, Alex (2020-03-24). "India's coronavirus lockdown and its looming crisis, explained". Vox (अंग्रेज़ी में). मूल से 28 मार्च 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2020-03-25.
6. ↑ Bureau, Our. "PM Modi calls for 'Janata curfew' on March 22 from 7 AM-9 PM". @businessline (अंग्रेज़ी में). मूल से 20 मार्च 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 March 2020.
7. ↑ "India's 1.3bn population told to stay at home". BBC News (अंग्रेज़ी में). 2020-03-25. मूल से 31 मार्च 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 March 2020.
8. ↑ "पूरा देश लॉकडाउन की ओर, 31 मार्च से पहले फिर हो सकता है जनता कर्फ्यू का आह्वान". अमर उजाला. अभिगमन तिथि 25 जुलाई 2020.
9. ↑ "कोरोना का प्रभाव, 2020 में 4.5 फीसदी GDP का अनुमान: सरकार". अमर उजाला. मूल से 9 जुलाई 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 जुलाई 2020.
10. ↑ "At -23.9%, GDP Contracts For First Time In Over Four Decades". NDTV.com.
11. ↑ "Coronavirus Update (Live): 25,592,318 Cases and 853,437 Deaths from COVID-19 Virus Pandemic - Worldometer". www.worldometers.info (अंग्रेज़ी में).
12. ↑ "At -23.9%, GDP Contracts For First Time In Over Four Decades". NDTV.com.
13. ↑ अहमद, ज़ुबैर (1 मई 2020). "कोरोना महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था स्वदेशी की तरफ़ जाएगी?". BBC News हिंदी. मूल से 27 जून 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 जुलाई 2020.
14. ↑ शर्मा, अभय. "कैसे इस बुरे वक्त में हमारे गांव देश की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचा रहे हैं". सत्याग्रह. अभिगमन तिथि 25 जुलाई 2020.
15. ↑ "कोविड-19: भारत में 'लॉकडाउन' से प्रवासी कामगारों पर भारी मार". संयुक्त राष्ट्र समाचार. 2 अप्रैल 2020.
16. ↑ "At -23.9%, GDP Contracts For First Time In Over Four Decades". NDTV.com.
17. ↑ राय, निधि (13 मार्च 2020). "कोरोना वायरस से भारत की आर्थिक परेशानियाँ कितनी बढ़ीं?". बीबीसी हिन्दी. मूल से 4 जून 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 जुलाई 2020.

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 7, July 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1107103 |

18. ↑ "क्या सरकार जल्द ही करने वाली है एक और आर्थिक पैकेज का ऐलान?". ज़ी न्यूज़. 22 जून 2020. मूल से 23 जून 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 जुलाई 2020.
19. ↑ "At -23.9%, GDP Contracts For First Time In Over Four Decades". NDTV.com.
20. ↑ "6 फैक्टर जिससे पता चलता है कि देश की इकॉनमी में सुधार की शुरुआत हो चुकी है". नवभारत टाइम्स. अभिगमन तिथि 25 जुलाई 2020.
21. ↑ "At -23.9%, GDP Contracts For First Time In Over Four Decades". NDTV.com.

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor
Impact Factor: 8.118

doi crossref

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

9940 572 462 6381 907 438 ijirset@gmail.com

Scan to save the contact details

www.ijirset.com